New Airports in the country

178. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up new airports in the country considering, the demands from various States; and

(b) if so, what are the places selected for construction of new airports in the country and the amount allocated by Government for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Development of new airports is taken up depending upon the demand from the airlines and the capacity available with them, traffic potential and the availability of resources for development of infra-structural facilities.

(b) Presently the National Airports Authority is developing new airports at Shimla (Himachal Pradesh), Calicut (Kerala) and Agatti (Lakshadweep Island). The likely cost of development of these airports is indicated below against each of them:

(i) Shimla....Rs. 4.21 crores
(ii) Calicut....Rs. 22.41 crores
(iii) Agatti....Rs. 6.81 crores.

महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते

179. **श्री शरद यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को अन्य निगमों के कर्मचारियों की भांति वेतन और भत्ते दिए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) इस संबंध में नियमों को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जाएगा;

(घ) क्या इस संबंध में कोई समिति गठित की गई है;

(ङ) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, उप-प्रबंधक (प्रचार), सहायक प्रबंधक (जन सम्पर्क) और आशुलिपिकों आदि को वेतन और भत्ते केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों के अनुसार मिल रहे हैं या निगमों के वेतनमानों के अनुसार;

(च) यदि उन्हें निगमों के वेतनमानों के अनुसार वेतन और भत्ते मिल रहे हैं तो उनका श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(छ) प्रत्येक मामले में इन दोनों वेतनमानों का अन्तर कितना है;

(ज) क्या निगम के अन्य कर्मचारियों की भी इन अधिकारियों के समान वेतन दिए जाने की संभावना है; और

(झ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) निगम के प्रबंध निदेशक को वेतन और भत्ते सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को देय वेतन और भत्तों के अनुसार दिए जा रहे हैं। उप-प्रबंधक (प्रचार), सहायक प्रबंधक (जन संपर्क) तथा स्टेनोग्राफर आदि को वेतन और भत्ते केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे हैं।

(च) निगम के प्रबंध निदेशक अनुसूची "क" के वेतनमान अर्थात 4,500–125–5000 रु० में आते हैं तथा उन्हें इस वेतनमान पर तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित औद्योगिक मंहगाई भत्ता और अंतरिम राहत दी जाती है।

(छ) केन्द्र सरकार में प्रबंध निदेशक का कोई पद नहीं है। इसकी वजह से, उनके मामले में तथा अन्य के संबंध में उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।